No 1/7/2017-समन्वय.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

छठा तल, 'बी' विगं, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांकः 06 अक्टुबर, 2017

सेवा में,

1. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष,
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष,
3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य,
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य,
5. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य,

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 16.8..2017 को 15:00 बजे सम्पन्न 98वीं बैठक मे हुइ चर्चा का कार्यवृत्त

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का उल्लेख करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग की 98वीं बैठक आयोग के सम्मेलन कक्ष, लोकनायक भवन, नई दिल्ली मे दिनांक 16.8..2017 को 15:00 बजे सपन्न हुई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई। बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(के.डी. बंसौर)श्रीमती
निदेशक

98वीं बैठक की कार्यवृत की एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि बैठक मे लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध मे जानकारी प्रत्येक संबधित एकक/कार्यालय द्वारा दिनांक 23.10.2017 तक अंवश्य ही समन्वय एकक को भेज दी जाए।

1. निदेशक (अनुसंधान एकक–III & IV)
2. उप सचिव ( अनुसंधान एकक– I & II)
3. अवर सचिव (समन्वय, स्थापना एवं अनुसंधान एकक– IV)
4. सहायक निदेशक (प्रशा. एवं अनुसधान एकक– III)/ सहायक निदेशक, (राजभाषा एवं अनुसंधान एकक–I & II)

प्रतिलिपिः 98वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषितः

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य (श्री एच.के.डी) के निजी सहायक
4. माननीय सदस्य (श्री एच.सी.वी) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य (श्रीमती एम.सी.आई) के निजी सहायक सचिव
6. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव के निजी सहायक
8. निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/भुवनेश्वर/जयपुर/रायपुर/रांची/शिलांग।
9. आयोग की एनआईसी वेबसाइट पर डालने हेतु।

No.1/7/2017-Coord.
**Government of India**
**National Commission for Scheduled Tribes**
******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 6th October, 2017

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
5. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

**Subject: Summary Record of discussions of 98th Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 16.8.2017 at 15:00 Hrs.**

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 97th meeting of the National Commission for Scheduled Tribes was held on 16.8.2017 at 15:00 Hrs. in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(K.D Bhansor) Mrs.
Director

Copy of the Summary Record of discussions of 98th meeting of NCST is forwarded to the following Officers with request that information about action taken on the decision taken in the meeting concerning each Unit/Office may be furnished to Coordination Cell by 23.10.2017 positively:

(i) Director (RU-III & IV)
(ii) Deputy Secretary (RU-I & II)
(iii) Under Secretary (Coordination, Estt.& RU-IV)
(iv) Assistant Director (RU-III & Admin)/AD (OL & RU-I & II)

Copy of Summary Record of discussion of 98th meeting is forwarded for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PA to Hon'ble Member (Shri HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (Shri HCV), NCST
5. PS to Hon'ble Member (Smt. MCI), NCST
6. Sr.PPS to Secretary, NCST
7. PA to Joint Secretary, NCST
8. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
9. NIC, NCST for uploading on the website.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 98वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

(फाईल सं. 1/7/2017–समन्वय)

दिनांक : 16.8.2017 समय : 15.00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
7. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
8. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
9. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
10. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
11. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

| | |
|---|---|
| **कार्य सूची मद सख्या. 1**<br><br>**Agenda Item No. 1** | प्रेस कतरन समाचार पत्र मिन्ट, दिल्ली संस्करण दिनांक 12.4.2017 मे प्रकाशित शीर्षक "महत्वपूर्ण बाघ आवासों में आदिवासियों के लिए कोई वन अधिकार नहीं"।<br><br>Press Clipping dated 12.4.2017 published in the Mint, Delhi edition under the caption "No forest rights for tribals in critical tiger habitats" |

**(PC/1/2017/MENV1/SEOTH/RU-IV)**

1.1 प्रेस कतरन समाचार पत्र मिन्ट, दिल्ली संस्करण दिनांक 12.4.2017 मे प्रकाशित शीर्षक "महत्वपूर्ण बाघ आवासों में आदिवासियों के लिए कोई वन अधिकार नहीं" पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया। तदनुसार, आयोग ने पत्र संख्या पीसी/1/2017/एमईएनवी 1/सीओटीएच/आरयू–4 दिनांक 17.5.2017 द्वारा राष्ट्रीय बाघ सरंक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मत्रांलय से जानकारी मांगी। तदोपरांत, सचिव, राष्ट्रीय

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूचित जनजाति आयोग ने, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पत्र सं0 1–7/93–पीटी(खंड।) दिनांक 28.03.2017, जो कि बाघ रेंज के राज्यों के मुख्य वन्य जीव वार्डनों को अनिवार्य/महत्वपूर्ण बाघ आवासों में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (जिसे यहां पर बाद में एफआरए के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अंतर्गत अधिकार देने से विरत रहने की सलाह देता है, के संदर्भ में दिनांक 04.07.2017 को बैठक की । बैठक का मसौदा कार्यवृत्त संलग्न है। बैठक में चर्चित बिंदु निम्न है:–

(क) 10 लाख रूपए प्रति परिवार अपर्याप्त है और इसे कम से कम 20 लाख रूपए प्रति परिवार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उल्लेख किया गया कि भारत सरकार के पास रखी हुई कैम्पा (क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण); [CAMPA] निधियां अनिवार्य/महत्वपूर्ण बाघ आवासों से अनुसूचित जनजातियो को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लायी जानी चाहिए। एनटीसीए पैकेज का वर्तमान विकल्प–। जो केवल नकद क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है, उसका उपयोग केवल तभी किया जाए यदि लोग स्वैच्छिक रूप से इसका चुनाव करते हैं।

(ख) संरक्षित क्षेत्रों एवं बाघ अभ्यारण्यों के अनुसूचित जनजातियो के लोगों के पुनर्स्थापन की स्थिति में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार को संरक्षित क्षेत्र या बाघ अभ्यारण्यों से सटे हुए क्षेत्र में 4 हेक्टेयर या अनुसूचित जनजाति के द्वारा वास्तविक कब्जा के अधीन क्षेत्र तक, जो कि कम हो, वैसी ही जमीन उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। यदि समान प्रकार की जमीन उपलब्ध न हो, तो संरक्षित क्षेत्रों और बाघ अभ्यारण्यों से अनुसूचित जनजाति के पुनर्स्थापन/पुनर्वास के लिए वास्तविक कब्जे के क्षेत्र का दोगुना या 8 हेक्टेयर जो भी कम हो उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। पुनर्स्थापन/पुनर्वास की सम्पूर्ण लागत कैम्पा से उद्भूत की जानी चाहिए।

(ग) नकद क्षतिपूर्ति या पुनर्स्थापन/पुनर्वास संपूर्ण प्रकिया तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए, इसमें असफल रहने की स्थिति में तुरन्त वन अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।

(घ) किसी भी वन निवासी अनुसूचित जनजाति सदस्य को उसके कब्जे के अधीन वन भूमि से रिक्त कराया या हटाया नहीं जाना चाहिए जब तक कि वन निवासी आदिवासी सदस्य को वैकल्पिक भूमि की मान्यता एवं अन्तरण पूर्ण नहीं हो जाता।

1.2 **उपरोक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत, आयोग ने निर्णय लिया कि उपरोक्त बिन्दुओं तथा प्रकरण पर राष्ट्रीय बाघ सरंक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मत्रांलय की एक बैठक की जाए।**

**[After detailed discussion on the matter, Commission decided to call a meeting of National Tiger Conservation Authority (NTCA) and Ministry of Environment, Forest and Climate Changes on the above points and matter.]**

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| | |
|---|---|
| कार्य सूची मद सख्या 2<br><br>**Agenda Item No. 2** | इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पंप डीलरशिप निरस्त करने के संबंध मे श्री सोनुपंत कालु निंबेकर, मालिक, त्रिंबकेश्वर पेट्रोलियम, त्रिंबकेश्वर, तालुका एवं जिला–नासिक (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 22.6.2015.<br><br>Representation dated 22.6.2015 received from Shri Sonupant Kalu Nimbekar, Proprietor, Trimbakeshwar Petroleum, Trimbakehwar, Taluka and Distt.-Nashik, (Maharashtra) regarding termination of Petrol Pump dealership by the Indian Oil Corporation Limited. |

**(SKNB/2/2015/MPNG1/SEOTH/RU-II (RU-I)**

2.1 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएँल), मुंबई द्वारा पेट्रोल पंप डीलरशिप को निरस्त करने के संबंध में श्री सोनुपंत कालु निंबेकर, मालिक, त्रिंबकेश्वर पेट्रोलियम, त्रिंबकेश्वर, तालुका एवं जिला–नासिक (महाराष्ट्र) से दिनांक 22/06/2015 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। अभ्यावेदन मे आरोप लगाया कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को परेशान करने के लिए आईओसीएल द्वारा पेट्रोल पंप की डीलरशिप को निरस्त किया गया। उसने अभ्यावेदन मे प्रस्तुत किया कि:–

1. उसकी डीलरशिप को निरस्त करना अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य का उत्पीड़न करना।
2. पूर्व में आईओसीएल के मिलावट रोधी सेल द्वारा दिनांक 16.10.2013 को निरीक्षण किया गया, उसी दिन मुंबई में स्थित, कॉर्पोरेशन के महाराष्ट्र राज्य कार्यालय द्वारा एक पूर्व निरीक्षण किया गया, जिसके द्वारा पेट्रोल पंप के सभी वितरण एकक सही पाए गए।
3. आवेदक पिछले 20 वर्षों से व्यवसाय चला रहा है और गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में कोई भी शिकायत नहीं थी।
4. यू/जी टैंकों और सभी अन्य उपकरणों की मरम्मत एवं देखरेख कॉरपोरेशन की अन्य एंजेसियों द्वारा की जाती है।
5. वितरण एककों के पूर्व निरीक्षण में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं पाई गई।

2.2 प्रकरण को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्र संख्या एसकेएनबी/3/2015/एमपीएनजी 1/एसईओटीएच/आर यू–2 दिनांक 10.7.2015 के द्वारा अध्यक्ष एवं प्रंबध निदेशक (सीएमडी) आईओसीएल. के साथ उठाया गया। आयोग के पत्र दिनांक 10.7.2015 के जवाब में, महा प्रबंधक (खुदरा बिक्री) आईओसीएल ने पत्र सख्या 4031/ए एम/एमएसओ/740–एनसीएसटी दिनांक 21.08.2015 के द्वारा जवाब दिया, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(क) त्रिंबकेश्वर पेट्रोलियम हमारा "बी" साइट रीटेल आउटलेट है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिंबकेश्वर में स्थित है। रीटेल आउटलेट को दिनांक 30.7.1993 को, मालिक के रूप में अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्री सोनुपंत कालु निंबेकर के अधीन अधिकृत किया गया था।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ख) दिनांक 16.10.2013 को, उपरोक्त रीटेल आउटलेट का मिलावट रोधी सेल (एएसी) द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, एम एस (पेट्रोल) वितरण एकक (मॉडलःएल एंड टी स्प्रींट जीटी 112123 बी वी 3 क्रम सं. एल एंड टी के जेड 2997) में अतिरिक्त अनधिकृत फिटिंग्स लगे हुए पाए गए थे।

(ग) गीलबारको–वीडर रूट (जीवीआर) से ओईएम (मूल उपकरण उत्पादक–पंप निर्माता) के प्रतिनिधि को रीटेल आउटलेट में बुलाया गया और उसने फिटिंग की जांच की ओर अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि उपरोक्त उल्लेखित फिटिंग्स अनधिकृत हैं और ओईएम उपकरण के भाग नहीं है। तत्पश्चात्, अनधिकृत फिटिंग्स सहित कंट्रोल कार्ड, एस एमपी एस कार्ड को डीलर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निकाल दिए गए और संदूक में बंद करके सील कर दिया गया। एएसी दल द्वारा उक्त उल्लेख करते हुए एक पत्र दिया गया और उपरोक्त पर स्पष्टीकरण मांगा।

(घ) रीटेल आउटलेट से उत्पाद के नमूने लिए गए और उपरोक्त वितरण एकक को सील कर दिया गया। बाद में प्रयोगशाला में नमूनों की जांच की गई और जांच के अनुरूप पाए गए।

(ड.) आउटलेट से निकाले गए अनधिकृत फिटिंग्स को कोयम्बटूर के ओईएम के कारखाने में भेजा गया और पार्ट की जांच को आंखों से देखने के लिए डीलर को उपस्थित रहने के लिए दिनांक 25.10.2013 के पत्र द्वारा कहा गया। पत्र को डीलर ने विधिवत रूप से स्वीकार किया। शुरू में डीलर ने जांच की तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया लेकिन बाद में कहा कि वह जांच में उपस्थित नहीं हो पाएगा।

(च) वितरण एकक के अनधिकृत पुर्जों की कोयम्बटूर के ओईएम कारखाने में दिनांक 14.11. 2013 को जांच की गई और दिनांक 15.11.2013 की रिपोर्ट द्वारा यह पुष्टि की गई कि अतिरिक्त लगा हुआ पार्ट ओईएम उपकरण का हिस्सा नहीं है।

(छ) मात्रा को कम वितरण करने के लिए वितरण एकक में अतिरिक्त अनाधिकृत फिटिंग्स मार्केटिंग विषय दिशा–निर्देश (एम डी जी) 2012 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लखंन करने वाला एक स्पष्ट मामला है और इसे गंभीर अनियमितता के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। एमडीजी 2012 के अनुसार इस प्रकार की गंभीर अनियमितता के लिए निर्धारित कार्रवाई प्रथम चरण में डीलरशिप को निरस्त करना है।

(ज) उपरोक्त को देखते हुए, एम डी जी 2012 के विभिन्न खंड़ों के अंतर्गत निरस्त करने के लिए दिनांक 10.3.2014 को कारण बताओं नोटिस (एस सी एन) जारी किया गया। डीलरशिप ने दिनांक 11.4.2014 के पत्र द्वारा एस सी एन का जवाब दिया। डीलर का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसको देखते हुए, दिनांक 19.8.2014 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक वैयक्तिक सुनवाई डीलर को दी गई। सुनवाई में, डीलर ने एस सी एम में दिए गए जवाब को ही फिर से दोहराया। इसको देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेने के बाद, डीलरशीप को दिनांक 11.2.2015 के पत्र द्वारा निरस्त किया गया।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(झ) डीलर ने आरओ में विक्रय को रोकने के विरूद्ध राहत की मांग करते हुए आईओसीएल के विरूद्ध सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय में रेगुलर सिविल सूट सं. 25/2014 दर्ज किया है।

(ञ) माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.02.2015 में बताया कि जैसे कि डीलरशिप निरस्त करने का आदेश वादी को पहले ही दिया गया था, निषेधाज्ञा की अस्थायी दावा बेवजह हैं, जिसे पेश किया गया।

2.3 आयोग ने आईओसीएल के पत्र दिनांक 21.8.2015 की प्रति सूचनार्थ एवं टिप्पणी के लिए अभ्यावेदक को भेजी। उपरोक्त जवाब पर, अभ्यावेदक ने दिनांक 16.09.2015 का प्रत्युत्तर माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मामले पर दिनांक 22.4.2016 को सीएमडी, आईओसीएल के साथ एक बैठक निश्चित की। बैठक के कार्यवृत आयोग पत्र संख्या एसकेएनबी/3/2015/एमपीएनजी 1/एसईओटीएच/आर यू–2 दिनांक 02.05.2016 के द्वारा सी एम डी, आई ओसीएल, मुंबई को भेजा। उपरोक्त कार्यवृत में आयोग ने आवेदक के नाम में पेट्रोल पंप को निरस्त करने के लिए पहले लिए गए निर्णय तथा अपनाई गई प्रक्रिया में पाई गई गलतियों को ध्यान में रखते हुए उसके पक्ष में उसको बहाल रखने की समीक्षा करने के लिए आईओसीएल को सलाह दी। इसके अलावा, विश्वास करने का यह एक मजबूत कारण है कि यह सब अनुसूचित जनजाति को आंबटित, जो पिछले 20 वर्षों से व्यवसाय में है, को परेशान करने के उद्देश्य से किया गया है तथा पहले उसके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है। आयोग ने तद्नुसार आदेश दिए। आईओसीएल द्वारा लिए गए निर्णय तीन सप्ताह के भीतर आयोग को सूचित किया जाए असफल होने पर इस संबंध में एक और बैठक सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराई जाएगी।

2.4 दिनांक 22.04.2016 को आयोजित आयोग की बैठक के कार्यवृत्त के जवाब में, आईओसीएल ने पत्र संख्या 4031/ए एम/एमएसओ/740–एनसीएसटी दिनांक 13.05.2016 के द्वारा जवाब दिया जो उनके पूर्व के दिनांक 21.08.2015 के जवाब का अनुवर्ती है। आईओसीएल के उपरोक्त जवाब की प्रति सूचनार्थ अभ्यावेदक को भेजी गई और उसने आयोग को दोबारा दिनांक 07.06.2016 का प्रत्युत्तर दिया। माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 27.07.2016 को 12:00 बजे सीएमडी, आईओसीएल. के साथ दूसरी बैठक सुनिश्चित की। तद्नुसार, आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों को एक सिटिंग नोटिस जारी की। उपरोक्त बैठक में मामले की चर्चा हुई और बैठक का कार्यवृत्त आयोग के पत्र संख्या एसकेएनबी/3/2015/एमपीएनजी 1/एसईओटीएच/आर यू–2 दिनांक 29.08.2016 द्वारा आईओसीएल को भेजा गया, जिसमें आयोग ने आईओसीएल को श्री सोनुपंत कालु निंबेकर को पेट्रोल पंप बहाल रखने की सलाह दी, क्योंकि अनुसूचित जनजाति मालिक को परेशान करने के विचार से निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते हुए, आईओसीएल का मनमाना निर्णय है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से पत्र प्राप्त होने के सात दिन के भीतर, असफल होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के तहत आईओसीएल के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी। कार्यवृत्त की एक प्रति सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी उसके स्तर पर उचित कार्रवाई करने हेतु भेजी गई है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2.5 इस संबंध में, आईओसीएल ने दिनांक 22.04.2016 और 27.07.2016 को आयोग में हुई बैठको के कार्यवृत्त के संदर्भ में, अपने पत्र संख्या एमएसओ/एनसीएसटी/त्रिंबकेश्वर दिनांक 10.10.2016 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि आईओसीएल ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (सी) सं. 9186/2016 दाखिल की।

2.6 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सिविल) सं. 2016 का 9186 में आईओसीएल ने आयोग को प्रतिवादी सं. 1 बनाया गया है। आईओसीएल ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष, नीचे दिए गए बिन्दुओं के अनुसार अनुरोध किया है:

(क) कानून में इसकी शक्तियॉ एवं प्राधिकार अवैधानिक होने के कारण प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दिनांक 22.06.2015 को दिए गए अभ्यावेदन/शिकायत के अनुसरण में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जारी दिनांक 02.05.2016 (जिसमें 22.04.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त शामिल है) के साथ–साथ दिनांक 29.08.2016 (जिसमें 27.07.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त शामिल है) की संसूचनाओं को निरस्त एवं अपास्त करते हुए, रिकॉर्ड मांगते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति की एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देष जारी करें।

(ख) कानून और संविधान द्वारा बाध्य प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए दिनांक 22.06.2015 को अभ्यावेदन/शिकायत से व्युत्पन्न सभी कार्यवाहियों को निरस्त एवं अपास्त करते हुए एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करें।

(ग) प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दर्ज दिनांक 22.06.2016 की शिकायत को निरस्त एवं अपास्त करते हुए एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करें।

(घ) यह निर्देश दे कि अभ्यावेदक, प्रतिवादी सं. 2 के डीलरशिप को निरस्त करने के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिए गए निष्कर्ष अधिकार क्षेत्र बिना एवं गैर–बाध्यकारी हैं अतः नॉन–ऐस्ट है। और

(ड.) माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जो भी उपयुक्त और उचित समझे, ऐसा कोई दूसरा या अन्य आदेश पारित करें।

2.7 **न्यायालय के मामले के जवाब को तैयार करते समय, यह महसूस किया गया कि पूर्व उपाध्यक्ष महोदय की सलाह विभिन्न कारणो से पुनर्विचार योग्य है। तदनुसार, आयोग ने निर्णय लिया कि इस मामले को आगे नही बढ़ाया जाए और पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा दी गई सलाह को आयोग ने निरस्त किया।**

**[While preparaing response to Court case, it was felt that advice of former Vice-Chairperson appears to merit review. Accordingly, the Commission decided not to press with the matter further and rescinded the advice given by the former Vice-Chairperson.]**

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| | |
|---|---|
| कार्य सूची<br>मद सख्या 3 | पिता के नाम के बिना बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई। |
| **Agenda Item No. 3** | Difficulty in obtaining Caste Certificate for the children without name of father. |

**(AK/1/2017/MSJE1/DEOTH/RU-II)**

3.1 निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ने पत्र संख्या 17020/27/2017–एससीडी (आर.एल.सेल) दिनांक 6.7.2017 द्वारा श्रीमती मेनका सजंय गांधी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के पत्र संख्या 4/एम/कैब/17–18 दिनांक 11.4.2017 की एक प्रति अग्रेषित (प्रतिलिपि संलग्न) करते हुए उपरोक्त प्रकरण पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को टिप्पणिया देने का अनुरोध किया।

3.2 माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के पत्र में यह बताया गया है कि विवाह विच्छेद और पति तथा पत्नी के बीच अलगाव होना एक सच्चाई है जिसे हम नजरदांज नही कर सकते। हमे इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि प्रकियाओं/कानूनों मे कुछ कमियां होने के कारण ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं की उनके अधिकार तथा पात्रता प्राप्त नही होते। कई महिलाओं को तो उनके बच्चो को पिता के नाम के बिना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने मे समस्याएं होती हैं।

3.3 **उक्त प्रकरण पर आयोग ने भारत सरकार, गृह मत्रांलय के "अन्तर्जातीय विवाहित जोडों की सन्तान की स्थिति" विषय पर सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र संख्या 39/37/73–एससीटी–1 दिनांक 21.5.1977 (प्रति संलग्न) जो स्वतः स्पष्ट है पर विचार विमर्श किया तथा आयोग की सलाह है कि इस पत्र के निर्देशों का पालन किया जाना उचित होगा।**

[Commission discussed the instructions on "Caste staus of the offsprings of inter-caste married couples" issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs to the Chief Secretaries of all States/UTs, vide letter No. 39/37/73-SCT-1 dated 21.5.1977 (copy enclosed), which is self explanatory on the above issue and advised that it would be approporiate that instructions issued in the letter be followed ].

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्य सूची मद
**Additional Agenda Item**

| | |
|---|---|
| कार्य सूची मद सख्या 1 | दिनांक 18/05/2017 की प्रेस कतरन, मिलेनियम पोस्ट, दिल्ली संस्करण मे "केंदु के पत्तों के लिए कलह" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। |
| **Agenda Item No. 1** | Press Clipping dated 18.5.2017 published in Millennium Post, Delhi edition under the caption "At loggerheads for kendu leaves" |

**(33/Press Clipping/8/2017/RU-III)**

1.1 दिनांक 18/05/2017 प्रेस कतरन, मिलेनियम पोस्ट, दिल्ली सस्करण मे "केंदु के पत्तों के लिए कलह" शीर्षक के अंर्तगत प्रकाशित हुआ। तदनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर प्रकरण पर संज्ञान लिया तथा सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 2/6/2017 को मामले पर चर्चा करने के लिए प्रधान सचिव, वन विभाग, ओडीशा सरकार, सचिव, वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार तथा प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड को बुलाया।

1.2 प्रधान सीसीएफ (केंदु पत्ता), ओडीशा सरकार तथा एपीसीसीएफ (एनटीटीपी), महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा हुई। चर्चा का कार्यवृत का प्रारूप संलग्न है। प्रारंभिक बैठक में निम्नलिखित बिन्दु उभर कर आये, जो आयोग के समक्ष रखे गये :–

(क) केंदु पत्तों के संबंध मे ओडिशा मे अनुसूचित क्षेत्रो मे अनुसरण किया जा रहा केन्द्रीय विनियमित केंदु व्यापार का वर्तमान चलन, पेसा अधिनियम (Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA) के अनुरूप नहीं है।

(ख) वन अधिकार अधिनियम (The Scheduled Tribes and othe Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (Forest Rights Act) के अनुसार, ग्राम सभा के पास केंदु के पत्तों के स्वामित्व, संग्रहण, उपयोग तथा नष्ट करने का अधिकार है।

(ग) ओडीशा सरकार को 2014–15 मे महाराष्ट्र सरकार के अधिनियमो के समान ओडीशा मे अनुसूचित क्षेत्रो मे जनजातीय लोगो को केंदु के पत्तों के स्वामित्व, संग्रहण, विक्रय के अधिकारो को देने के लिए संविधान की पॉचवी अनुसूची के पैरा 5(1) के अंतर्गत राज्यपाल मे निहित विशेष शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

1.3 आयोग ने उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की तथा यह निश्चित किया कि अंतिम निर्णय लेने से पहले, महाराष्ट्र तथा ओडीशा राज्यो के वन विभाग **(Forest Department)** एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग **(Tribal Development Department)** के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अनुसूचित जनजातियो के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 मे बनाए गए अधिनियमों की वास्तविकता तथा कियान्वयन की जानकारी हेतु, महाराष्ट्र राज्य के ग्राम सभा प्रतिनिधियो तथा महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग **(Tribal Development Department)** तथा वन विभाग **(Forest Department)** के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र राज्य मे बैठक आयोजित की जाए। तदुपरांत, ओडीशा राज्य मे वहां के ग्राम सभा प्रतिनिधियो तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ओडीशा राज्य मे बैठक आयोजित की जाए।

**[Above points was dicussed in detail and Commission decided that before taking a final decision, the matter should be discussed with the Senior Offcers of the Forest Department and Tribal Development Department of the States of Maharashtra and Odisha along with Scheduled Tribes representatives. To assess the reality and implementation of the enactments of Government of Maharashtra in 2014-15, a meeting should be organized with the Senior Officers of Forest Department and Tribal Development Department of Government of Maharashtra along with representatives of Gram Sabhas at Maharashtra State. Thereafter, a meeting should be organized with the Senior Officers of Forest Department and Tribal Development Department, Government of Odisha along with Gram Sabha representative at Odisha State].**

(नन्द कुमार साय)
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

PROCEEDINGS OF THE MEETING HELD ON 4.7.2017 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SECRETARY, NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES REGARDING PRESS CLIPPING UNDER THE CAPTION "NO FOREST RIGHTS FOR TRIBALS IN CRITICAL TIGER HABITATS".

---

A meeting was held on 4.7.2017, under Chairmanship of the Secretary, National Commission for Scheduled Tribes, Government of India, in context of a National Tiger Conservation Authority's letter No.1-7/93-PT(Vol.I) dated 28.3.2017 which had advised the Chief Wildlife Wardens of tiger range States to refrain from conferring rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (hereinafter referred to as the FRA) in core/critical tiger habitats. A list of participants is annexed.

2. At the outset, the Chairman welcomed the participants which was followed by a round of introductions of members present. The Assistant Inspector General of Forests, National Tiger Conservation Authority gave a short presentation on the background of the letter issued as follows;

a. The NTCA, vide its aforesaid letter, had advised Chief Wildlife Wardens of Tiger States to refrain from conferring rights in "Critical Tiger Habitats", already notified by State Governments under Section 38V (4)(i) of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

b. This was extremely essential to avoid confusion at the level of field formations, since the said Section [(read along with 38V (5)] already provides at length the process for identification/settlement of rights in such areas.

c. It is further stated that provision for notification of "Core Critical Tiger Habitat" is a very special dispensation provided only in Chapter IV B of the Wildlife (Protection) Act, 1972, based on the amendment to the said Act in 2006, to take care of the special/territorial land tenure dynamics of the critically endangered tiger with marked/ aggressive intra and inter specific interactions.

d. The provision for notifying "Critical Wildlife Habitat" is contained only in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. Thus, the communication under reference from the NTCA was essential to prevent confusion amongst the bonafide people and Field Managers.

e. Conferring rights under "Critical Wildlife Habitat" for core/critical tiger habitats of tiger reserves involves invoking Section 4(2) of the FRA, amounting to a repetitive process which is already being taken care by the Wildlife (Protection) Act, 1972 (read with the FRA).

f. It was discussed critically that in declaring an area as a National Park or Wildlife Sanctuary, a two stage process has been described by the Wildlife (Protection) Act, 1972:

(i) The intent to declare an area as a Sanctuary (Section 18) or a National Park {Section 35(1)}.

(ii) Final notification as per Section 26A for a wildlife sanctuary and Section 35 (4) in respect of a National Park.

The entire process involves settlement of rights which is detailed in section 19 to 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972. Once final notification has been issued, no further settlement of rights can be carried out.

g. In addition, section 38V (5) of the WL(P)A, 1972 clearly describes the process of settlement of rights. In fact, it is pertinent to mention at this juncture, that the FRA, 2006 as per provisions of section 4(2)(b) borrows procedure from the WL(P)A, 1972 in so far as settlement of rights of tribals and other forest dwellers are concerned, and hence, derives strength from the WL(P)A.

h. However, the National Tiger Conservation Authority observed during supervisory field visits in tiger reserves of Maharashtra, that rights under the FRA were being conferred even after the final notification as outlined above had been issued, besides being notified as a Critical Tiger Habitat under Section 38V (4)(i) of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

3. The Secretary, NCST was appraised that nearly 44000 families still reside in core/critical tiger habitats of India's tiger reserves. It is, therefore, desired that the matter should be dealt carefully so that the welfare of tribals and tiger conservation are not at the expense of each other.

4. The Additional Director General of Forests and Member Secretary, National Tiger Conservation Authority explained in detail that the Government of India, through the ongoing Centrally Sponsored Scheme of Project Tiger has an elaborate rehabilitation package which can be availed on a voluntary basis by tribals living inside core/critical tiger habitats as per provisions of Section 38 V

(5) of the Wildlife (Protection) Act, 1972. He also informed members that the said package is in process of being revised which however, shall take time as concurrence of the Ministry of Finance shall have to be obtained. The existing package with its options was described as follows;

Option I – Payment of the entire package amount (Rs. 10 lakhs per family) to the family in case the family opts so, without involving any rehabilitation and relocation process by the Forest Department.

Option II – Carrying out relocation and rehabilitation of village from protected area and tiger reserve by the Forest Department.

5. The Secretary, NCST opined that the amount of Rs. 10 lakhs per family is insufficient and needs to be enhanced to at least to Rs.20.00 lakh per family. He mentioned that the CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) funds lying with the Government of India should be utilized for the purpose of resettling tribals from core/critical tiger habitats. The existing Option-I of the NTCA package which entails only cash compensation should be exercised only if the people opt voluntarily.

6. In case of relocation of tribal people from protected areas and tiger reserves, each tribal family should be provided similar land upto 4 hectare or area under actual occupation by the tribal, whichever is less, adjoining to the protected area or tiger reserves. In case land of similar nature is not available, then double the area of actual occupation or 8 hectares, whichever is less should be provided for relocation/ rehabilitation of tribals from protected areas and tiger reserves. The entire cost towards relocation/rehabilitation should be borne from CAMPA.

7. The entire exercise of cash compensation or relocation/rehabilitation should be carried out within a period of three years, failing which the forest rights should be conferred immediately.

8 No member of forest dwelling Scheduled Tribes should be vacated or removed from forest land under his/her occupation till recognition and transfer of alternate land to the forest dwelling tribal person is completed.

**********

ANNEXURE

## National Commission for Scheduled Tribes

**List of participants attended the meeting held on 04.07.2017 at 03.15 P.M under the Chairmanship of Secretary, NCST regarding press clipping dated 12.04.2017 in the Mint, Delhi edition caption no forest rights for tribals in critical tiger habitats.**

**I** **National Commission for Scheduled Tribes**

| Sl. No. | Name & Designation | |
|---|---|---|
| 1. | Shri Raghav Chandra<br>Secretary | In Chair |
| 2. | Shri Sisir Kumar Ratho<br>Joint Secretary | |
| 3. | Shri D.S. Kumbhare<br>Under Secretary | |

**II** **Ministry of Tribal Affairs**

NIL

**III** **M/o Environment Forest & Climate Change**

NIL

**IV** **National Tiger Conservation Authority**

1. **Dr. Debabrata Swain**
   **ADGPT & Member Secretary**

2. **Dr. Vaibhav C. Mathur**
   **AIG**

SE/10/(R)

04/M/Cab.

Dy. No. 796 /VIP/M(SJ&E)
Dated 13/4/17


मेनका संजय गांधी

*Maneka Sanjay Gandhi*

मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001

**MINISTER**
**MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT**
**GOVERNMENT OF INDIA**
**NEW DELHI-110001**


APRIL 11, 2017

12.4.17

**Dear Shri Gehlot,**

Last year I had received representations from women who have separated from their husbands and wanted the name of the father to be deleted from the passports of their children whose custody has been given to the mother. I had taken up this matter with Hon'ble Minister for External Affairs and we had set up a joint group to examine these issues. After due deliberations, the Passport Guidelines were amended to provide for only the name of the mother to be specified in the child's passport on the basis of a self-declaration by the mother. Since these amended guidelines came into force, may women have been able to get the passports of their children issued/amended.

2. Breakdown of marriages and separation of husband and wife is now a reality which we cannot ignore. What we need to appreciate is the fact that women in such situations often do not get their rights and entitlements due to certain loopholes in the procedures/laws. We are working to plug these loopholes suitably.

3. I have been approached by several women who are having problems in getting caste certificates for their children without the name of the father from the jurisdictional offices. Keeping in view the sensitivity of the single / separated mother, we need to make a provision for this purpose by suitably changing the rules/guidelines. I shall be grateful if you could look into this matter for an early resolution. I shall be available for any assistance in this regard.

With regards,

Yours sincerely,

(Smt. Maneka Sanjay Gandhi)

**Shri ThaawarChand Gehlot,**
Hon'ble Minister of Social Justice & Empowerment,
202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
**New Delhi**


Off.: Room No. 353, 'A' Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001, Tel.: 23074052-54, Fax: 23387384
Resi.: 14 Ashoka Road, New Delhi-110001, Tel.: ...

No. 39|37|73-SCT. I

Government of India|Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs|Grih Mantralaya

To

The Chief Secretaries of all State Governments & Union Territory Administrations.

New Delhi-110001., the 21 May, 1977|31 Vaisakha, 1899

SUBJECT:—*Caste status of the offsprings of inter-caste married couples.*

Sir,

I am directed to say that enquires about the caste status of the offsprings of the inter-caste married couples, have been sought from this Ministry by various State Governments|Union Territory Administrations from time to time. Accordingly this question has been receiving the attention of this Ministry for quite some time. A set of legal views on the caste status of such offsprings was already brought out vide this Ministry's letter of even number dated the 4th March, 1975. The matter has, however, been further examined and the comprehensive legal position about the status of the offsprings born to couples where one or both of the spouses is|are member(s) of Scheduled Castes and or Scheduled Tribes, is given in the enclosed Annexures (A to D).

2. It is requested that these instructions may be circulated among all the authortiies empowered to issue Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates.

Yours faithfully,

(O. R. SRINIVASAN)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

No. 39|37|73-SCT.I, Dated the 21 May, 1977

31 Vaisakha, 1899

Copy to :—

1. All Ministry's|Departments of the Government of India.

2. All attached and subordinate offices of the Ministry of Home Affairs.

3. The Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011.

4. The Subordinate Services Commission, R. K. Puram, New Delhi-110022.

(O. R. SRINIVASAN)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

ANNEXURE—A

*Legal views on the status of the offspring of a couple where one of the spouses is a member of a Schedule Caste*

The general position of Law as to that effect of marriage between parties who are Hindus and one of whom belongs to the Scheduled Castes in that under the ancient Hindu law, generally, inter-caste marriage was looked down upon by the propounders and commentators. Some of the authorities, however, reluctantly permitted marriage between a male caste Hindu with a Shudra female and included it in the list of Anuloma marriages although it was stated that in the wedding with a Shudra wife, the ceremony should be performed wihout Mantras. The children born out of such marriage by a caste Hindu with a woman of an inferior caste had neither the caste of the father nor the status of his Savarn Aurasas-meaning the son born of a caste Hindu wife. They were termed as Anulomaja and belonged to an intermediate caste higher than that of their mother and lower than that of their father. Yajnavalkya omits the son of Brahmin by a Shudra wife from the list of sons mentioned by Manu. Pratiloma marriages, i.e. marriages between woman of a superior caste with a man of an inferior caste, were altogether forbidden and no rites were prescribed for them in Grihya Sutra and persons entering into such marriages were degraded from the caste.

2. After the passing of the various statutory enactments relating to the Hindu law, such as, the Hindu Marriages Act, 1955, the Hindu Succession Act, 1956 and the Hindu Minority & Guardianship Act, 1956, customary ban on inter-caste marriages in either way, has been lifted by the statutory enactments. Under the Hindu Marriage Act, any two Hindus of different sex, irrespective of their caste may enter into a valid marriage unless such marriage is prohibited by the Statute itself. According to the above three Statutes, all children either legitimate, or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, a Budhist, a Jain or a Sikh by religion and who are brought up as members of the tribe, community, group or family to which their parents belong or belonged, are to be treated as Hindus. In view of the above, the off-springs of marriage between the caste Hindu and a member of the Scheduled Caste community, are Hindus and like the offspring of marriage in the same caste, are entitled to succeed to the properties of their parents. But the status of his or her parent belonging to the higher caste or a question arises as to whether such a child will acquire the property that of the parent belonging to the Scheduled Caste. On this point, we have not come across any direct case law. But we feel that the ratio of the decision in *Wilson Read Vs. C. S. Booth* reported in AIR 1958 Assam 128 would apply to such cases. It is stated at page 182.

> "The test which will determine the membership of the individual will not be the purity of blood, but his own conduct in following the customs and the way of life of the tribe; the way in which he was treated by the community and the practice amongst the tribal people in the matter of dealing with the tribal people in the matter of dealing with persons whose mother was a Khasi and father was a European".

Similarly, in the case of *Muthuswamy Mudaliar Vs. Masilman Mudaliar*, reported in ILR 33, Madras, 342, the Court held:—

> "It is not uncommon process for a class or tribe outside the pale of caste to another pale and if other communities recognised their claim, they are treated as of that class or hastes. The process of adoption into the Hindu hierachy through caste is common both in the North and in the South India. As we have already pointed out, in the past there have been cases where people who judge from the purity of blood could not be Khasis, were taken into their fold or the orthodoxy did not stand in the way of their assimilation into the Khasi community".

3. The Supreme Court in *V. V. Giri Vs. D. S. Dora* reported in AIR 1959 S. C. 1318 (1327) held,—

> "...The caste—status of a person in the context would necessarily have to be determined in the light of the recognition received by him from the members of the caste into which he seeks an entry.

There is no evidence on this point at all. Besides the evidence produced by the appellant merely shows some acts by respondent I which no doubt were intended to assert a higher status; but unilateral acts of this character cannot be easily taken to prove that the claim for the higher status which the said acts purport to make is established. That is the view which the High Court has taken and in our opinion the High Court is absolutely right."

In view of the above observations by superior Courts, it can safely be concluded that the crucial test to determine is whether a child born out of such a wedlock has been accepted by the Scheduled Caste community as a member of their community and has been brought up in that surrounding and in that community or not. The nexus between the child and the community or class or caste is a real test irrespective of the fact whether the accommodating class or caste or community is Scheduled Caste community or a caste Hindu community. Even if the mother of the child is a member of the Scheduled Caste community, it is possible that the child is accepted by the community of his father and brought up in the surroundings of his father's relations. In that case, such a child cannot be treated as a member of the Scheduled Caste community and cannot get any benefit as such. Similarly, when the mother belongs to a higher caste and the father is a Scheduled Caste, the father may remain away from the Scheduled Caste Community and the child may be brought up in a different surrounding under the influence of his mother's relations and her community members. In such cases also, the child cannot be said to be a member of the Scheduled Caste community. In the alternative, where the child irrespective of the fact whether the father or the mother is a member of Scheduled Caste community, is brought up on the Scheduled Caste community as a member of such community, then he has to be treated as a member of the Scheduled Caste community and would be entitled to receive benefits as such.

4. As regards the marriages not registered and marriages not legally valid, it may be pointed out that registration is not mandatory for marriages under the Hindu law. Even under the Hindu Marriage Act, 1955, registration under Section 8 is optional and sub-section (5) provides that the validity of any Hindu marriage shall, in no way, be affected by the omission to make entry in the Marriages Register maintained under this Section. Section 7 provides that Hindu marriage may be soleminised in accordance with the customary rites and the ceremonies of either party thereto and, if such ceremony includes the Saptapadi, the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken. In view thereof, all those marriages though not registered but which have been solemnised in accordance with the procedure mentioned in this Section, are to be treated as valid marriages and our opinion mentioned in para 3 above will apply to the children born out of such valid but undersigned marriages.

5. As regards marriages which are not legally valid, it is clear that such children are illegitimate unless invalidity of marriage is due to grant of a decree of nullity by a Court in which case, provisions of Section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955, will apply. Under Section 6(b) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, the natural guardian of a Hindu minor has been stated to be—

"in case of an illegitimate boy or an illegitimate girl—the mother and after her the father"

6. It can be derived from this that the illegitimate children are generally brought up by the mother and in her own surroundings. Therefore, if the mother belongs to the Scheduled Caste and brings up the child within a Scheduled Caste community, the child can be taken as a member of the Scheduled Caste community. But in this case also the major factor for consideration is whether the child has been accepted by the Scheduled Caste community as a member of their community and he has been brought up as such.

7. The above are the general observations, however, each case has to be examined in the light of the circumstances prevalent in that case and final decision has to be taken thereof.

ANNEXURE—B

*Legal views on the status of the offsprings of a couple where one of the spouses is a member of a Scheduled Tribe*

The question has arisen whether the Off-spring born out of wedlock between a couple one of whom is a member of Scheduled Tribe and other is not, should be treated as a Scheduled Tribe or not.

2. It may be stated at the outset that unlike members of Scheduled Castes the members of Scheduled Tribes continues as such even after their conversation to other religion. This is because while Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 provides in clause 3 that only a member of Hindu or Sikh religion shall be deemed to be a member of Scheduled Caste, the Constitution (Scheduled Tribes Order, 1950)) does not provide any such condition. This view has been upheld by the Supreme Court in the case reported in AIR 1964 S.C. at p. 201.

3. It may be stated that unlike members of Scheduled Castes, members of Scheduled Tribes remain in homogenous groups and quite distinct from any other group of Scheduled Tribes. Each Tribe live in a compact group under the care and supervision of the elders of the Society whose words are obeyed in all social matters. A member committing breach of any prescribed conduct is liable to be excommunicated. The social custom has a greater binding force in their day to day life.

4. In the case of marriage between a tribal with a non-tribal, the main factor or consideration is whether the couple were accepted by the tribal socicty to which the tribal spouse belongs. If he or she, as the case may be, is accepted by the Society then their children shall be deemed to be Scheduled Tribes. But this situation can normally happen when the husband is a member of the Scheduled Tribe. However, a circumstances may be there when a Scheduled Tribe women may have children from marriage with a non-Scheduled Tribe man. In that event the children may be treated as Scheduled Tribes only if the members of the Scheduled Tribe Community accept them and terate them as members of their own community. This view has been held by the Assam High Court in *Wilsom Read* v. C. S. Booth reported in AIR 1958 Assam at p. 128, where it has been held—

> "The test which will determine the membership of the individual will not be the purity of blood, but his own conduct in following the customs and the way of life of the tribe; the way in which he has been treated by the Community and the practice amongst the tribal people in the matter of dealing with persons whose mother was a Khasi and father was a European".

Similarly, in the case of *Muthusamy Mudaliar* v. *Masilamam Mudaliar*, reported in ILR 33, Madras, 342, the court held—

> "It is not uncommon process for a class or tribe outside the pale of caste to another pale and if other communities recognised their claim they are treated as of that class or caste".

*Similarly, in V. V. Giri* v. *D. S. Dora*, reported in AIR 1959 S. C. 1318 (1327) the Court held—

> "The caste-status of a person in the context would necessarily have to be determined in the light of the recognition received by him from the members of the caste into which he seeks an entry".

5. As mentioned above, it is the recognition and acceptance by the society of the children born out of a marriage between a member of Scheduled Tribe with an outsider, which is the main determining factor irrespective of whether the Tribe is matriarchal or patriarchal. The final result will always depend on whether the child was accepted as a member of the Schedued Tribe or not.

6. The general position of law has been stated above. However, each individual case will have to be examined in the light of existing facts and circumstances in such cases.

No.33/Press Cliiping/8/2017/RU.III
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
---

Sub: Record of the "Preliminary Meeting of National Commission for Scheduled Tribes held on 2nd June, 2017 under the chairmanship of Secretary (NCST) on the news clipping in Millennium, Delhi, captioned At Loggerheads for kendu leaves".

---

Based on a news item which appeared in Millennium Post, Delhi dated 18th May, 2017, under the caption **"At loggerheads for kendu leaves",** a preliminary meeting under the chairmanship of Secretary(NCST) was held on 2nd June, 2017. The meeting was attended by Shri S.C. Mishra, IFS, Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) (Kendu leaf), Government of Odisha and Shri T.C. Choubey, IFS, Additional Principal Chief Conservator of Forests, Government of Maharashtra. Following are the highlights of the meeting:

(i) The PCCF (KL) Government of Odisha mentioned that Odisha has a unique case in trading of Kendu (Tendu) Leaves (KL) where processing of Kendu leaves is carried out by a specialised KL Wing of the Forest Department. He further mentioned that Odisha Kendu Leaves (Control of Trade) Act is under challenge in the Hon'ble High Court of Odisha.

(ii) The PCCF (KL), Odisha made a presentation about the benefits that are accruing to KL workers in the State. He also stated that KL trade has been deregulated in the Nabrangpur and Malkangiri districts of the State.

(iii) The Joint Secretary, NCST mentioned that as per provisions of Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act 1996 (PESA), the Panchayats in Scheduled Areas and the Gram Sabhas are endowed with the ownership of minor forest produce (MFP) which includes Kendu (Tendu) leaves. He further mentioned that as per rule 2 of the National Commission for Scheduled Tribes (Specification of other functions) Rules 2005, the Commission is mandated to take measures for conferring ownership rights in respect of minor forest produce to STs living in forest areas as well as full implementation of the provisions of Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act 1996.

(iv) Additional Principal Chief Conservator of Forests (NTFP), Government of Maharashtra informed that Governor of Maharashtra in exercise of the special

powers conferred under paragraph 5(1) of the Fifth Schedule of the Constitution has directed that Maharashtra (Transfer of ownership of minor forest produce in Scheduled Areas) Act and Maharashtra Minor Forest Produce (Regulation of Trade) (Amendment) Act 1997 shall apply to the Scheduled Areas with certain modifications. Accordingly, Maharashtra Minor Forest Produce (Regulation of Trade) Act has been amended in 2014. In addition, Governor Maharashtra vide their modification dated 15th October, 2016, has directed that all decisions for collection, use and disposal of MFP in Scheduled Areas of Maharashtra and use of income from sale proceeds shall be taken by Gram Sabhas or by a Committee made solely of the members of Gram Sabha. He mentioned that after the new enactment, the Gram Sabha decides whether to sell themselves or assign State Forest Department to collect, procure and sell on their behalf. He also presented copies of the following notifications issued by Government of Maharashtra in this regard.

| S.No. | Date | Reference | Subject |
|---|---|---|---|
| 1. | 25.6.2014 | Maharashtra Act No.XVIII of 2014. | Maharashtra Village Panchayats (Amendment & Continuance) Act 2014 |
| 2. | 5.7.2014 | Maharashtra Act No.XXXII of 2014 | Amendment of Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade) Act 2014. |
| 3. | 19.8.2014 | Notification issued by Governor of Maharashtra. | Amendment of Maharashtra Transfer of Ownership of Minor Forest Produce in the Scheduled Areas and the Maharashtra Minor Forest Produce (Regulation of Trade) Act 1997. |
| 4. | 30.10.2014 | Notification issued by Governor of Maharashtra. | Modifications to (i) Markets and Fairs Act 1862, (ii) Indian Forest Act 1927, (iii) Maharashtra Village Panchayat Act, (iv) Maharashtra Land Revenue Code 1966 and (v) Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 |
| 5. | 9.1.2015 | Notification issued by Governor of Maharashtra. | Addition of special proviso with regard to Tendu leaves in the Maharashtra Transfer of Ownership of Minor Forest Produce in Scheduled Areas and the Maharashtra Minor Forest Produce (Regulation of Trade) (Amendment) Act 1997. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | 15.10.2016 | Notification issued by Governor of Maharashtra. | Modifications to the Maharashtra Transfer of Ownership of Minor Forest Produce in Scheduled Areas and the Maharashtra Minor Forest Produce (Regulation of Trade) (Amendment) Act 1997. |

2 After detailed discussion, the following are the conclusions of the preliminary meeting.

(i) The existing practice of centrally regulating Kendu trade that is being followed in Scheduled Areas in Odisha in respect of Kendu leaves is not in consonance with the PESA Act.

(ii) As per provisions of Forest Rights Act, the Gram Sabha has the right of ownership, access to collection, use and disposal of Kendu leaves.

(iii) Government of Odisha should invoke special powers vested with Governor under paragraph 5(1) of the Fifth Schedule of the Constitution for endowing the rights of ownership, collection, sale of Kendu leaves to tribal people in the Scheduled Areas in Odisha similar to the enactments of Government of Maharashtra in 2014-2015.

(Raghav Chandra)
Secretary (NCST)